

सपने किसी पर निर्भर होकर नहीं, आत्मनिर्भर होकर पूरे किए जाते हैं।
- अज्ञात



ट्रंप अपने पहले भारत दौरे पर

उम्मीद है कि यह समझौता अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजारों तक पहले से कहीं ज्यादा पहुंच प्रदान करेगा। इससे पिछली गर्मियों में वापस लिए गए भारत के व्यापार लाभ बहाल हो सकते हैं।

मनोज।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने पहले भारत दौरे पर अगले महीने आ सकते हैं। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक यह यात्रा 24 से 26 फरवरी के बीच संभावित है। उनके आने से पहले फरवरी के दूसरे हफ्ते में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रिबर्ट लाइटहाइजर भारत आएंगे और केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मिलकर 10 अरब डॉलर की एक मेगा डील की रूपरेखा तैयार करेंगे जिस पर ट्रंप की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होंगे। उम्मीद है कि यह समझौता अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजारों तक पहले से कहीं ज्यादा पहुंच प्रदान करेगा। इससे पिछली गर्मियों में वापस लिए गए भारत के व्यापार लाभ बहाल हो सकते हैं। ट्रंप एक लंबी अवधि के व्यापार समझौते पर भी चर्चा करेंगे जिसमें एक मुक्त व्यापार

समझौता शामिल हो सकता है। साथ ही कई रक्षा डील होने की भी संभावना है। ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच चीन, अफगानिस्तान, ईरान और पाक प्रायोजित आतंकवाद पर बातचीत हो सकती है। संभव है अमेरिकी प्रेजिडेंट भारत दौरे के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में बीते सितंबर में ह्यूस्टन में आयोजित 'हाउडी मोदी' जैसे एक कार्यक्रम को संबोधित करें।

'हाउडी मोदी' को पीएम मोदी ने संबोधित किया था जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोग शामिल हुए थे। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय प्रवासी समुदाय अमेरिका में एक अहम वोट बैंक है। उनकी भारत यात्रा का एक बड़ा मकसद इस वोट बैंक को आकर्षित करना है। भारतीय प्रवासियों में गुजरातियों की संख्या

अच्छी-खासी है। संभवतः इसलिए वह अहमदाबाद जाने के इच्छुक होंगे। बहरहाल उनके आने से भारत को भी कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर राहत मिलेगी। अभी भारत सरकार को सीएए, एनआरसी और कश्मीर को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ रही है। 24 फरवरी से 30 मार्च तक जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान हमारी घेरेबंदी की तैयारी में है। ट्रंप की यात्रा से हमारे आलोचकों के बीच यह संदेश जाएगा कि भारत की इन नीतियों पर अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ है। दूसरी तरफ भारत 2009 के बाद सबसे धीमी विकास दर



का सामना कर रहा है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार को लेकर सतर्क हो गए हैं। पिछले दिनों अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने दावोस में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम में दुनिया भर के निवेशकों के बीच जिस तरह भारत की आलोचना की, उससे भारत के प्रति इन्वेस्टर्स के भीतर शंका और बढ़ी। ऐसे में ट्रंप की यात्रा और अमेरिका के साथ कारोबारी समझौते से निवेशकों का विश्वास हासिल करने में मदद मिल सकती है। बहरहाल भारत को उम्मीद रहेगी कि ट्रंप अपनी यात्रा के दौरान भारत के जीपीएस (जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस) स्टेटस को बहाल करेंगे। अगर वह ईरान के साथ कारोबार के मामले में बीच का कोई रास्ता निकाल कर हमें राहत दें, तो इस यात्रा की सार्थकता और बढ़ जाएगी।

जीवन और संघर्ष

अशोक वोहरा।

अक्सर जब हम किसी परेशानी में होते हैं और अपने जीवन के संघर्ष के बारे में सोचते हैं तब खुद को या तो अकेला महसूस करते हैं या खुद पर गर्व करते हैं। हकीकत में संघर्ष में या तो निखर जाओगे या बिखर जाओगे। गुजरा हुआ समय या आने वाला समय सिर्फ एक कल्पना है... वर्तमान में रहते हुए सिर्फ इस संघर्ष का सामना किया जा सकता है और जीवन के स्वरूप को बदला जा सकता है। व्यक्ति या स्थिति से सामना करने की क्षमता को विकसित करना भी जरूरी है। ये वो साधन हैं जो आपके संघर्ष को एक मजबूत नींव देने का काम करेंगे और सबसे पहले और जरूरी ये है की आप खुद पर भरोसा करना शुरू करें... एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना..।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

कोई महात्मा नहीं हो जाता!

जब विचारक और चिंतक जन्म लेते हैं तो उनके विचार विश्व में हवा की तरह फैल जाते हैं। इस हवा की मौजूदगी को नकारा या झुठलाया नहीं जा सकता। भारत ने भी कई विचारकों को जन्म दिया है और उनमें से एक महात्मा कहलाया। मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने की कहानी सिर्फ एक जीवनी नहीं है, सम्पूर्ण दर्शन है। इस दर्शन का विश्लेषण दृष्टा तक सीमित नहीं है और नई दृष्टि के उद्भव से जुड़ा है।

गांधी महात्मा कब बने और ऐसा क्या है जो उन्हें महात्मा बनाता है, इसे जानने के लिए गांधी को जानना जरूरी है। जिस युवा ने लंदन में वकालत पढ़ी उसका रहन-सहन जाहिर सी बात है एक जेंटलमैन वाला रहा। पाश्चात्य संस्कृति से जुड़कर आया एक युवक जब भारत के गांवों में नंगे पैर घूमने लगा, तो सारा देश उसके पीछे चल पड़ा। विलासिता भरी जिन्दगी जीने का विकल्प जिसके पास हमेशा मौजूद था, खुदको एक धोती में समेटना उसे महात्मा बनाता है। आचरण और व्यवहार ही नहीं गांधी के विचार ने उन्हें विश्व के महान विचारकों में से एक बना दिया। गांधी ने सत्य और अहिंसा के उस ध्येय को केंद्र में रखा, जिसे विश्व ने हमेशा असंभव माना था। जिस राष्ट्र के पास संसाधन नहीं थे, हथियार नहीं थे और लड़ने की क्षमता नहीं थी, उसे आत्मबल और संबल की शक्ति का आभास गांधी ने करवाया। जब राष्ट्र गांधी के साथ चला तो उसे अपनी शक्ति का पता लगा। अंग्रेजी हुकूमत के पास हर शक्ति से लड़ने के लिए हथियार थे लेकिन उनसे लड़ने के लिए नहीं, जिनके हाथ में कोई हथियार न हों।

इतिहास के पन्नों में गांधी, उनके आंदोलन और आंदोलन के परिणाम दर्ज हैं लेकिन जिस वक़्त एक गांधी नए विचार के साथ जमीन पर थे, उन्हें परिणाम नहीं पता था।

यही वजह है कि मांग और उत्पादन में इतने कम फर्क के बावजूद पर्याप्त बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती है। भारत विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं।

आज तक अमल नहीं कर पाए

अनिल पी जोशी।

ऊर्जा के सीमित उपयोग के लिए आयोजित अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियां आमतौर पर औपचारिकताओं में ही निपटा ली जाती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने हिस्से के विकास को रोकना चाहता हो। कोई भी कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगाना चाहता क्योंकि दुनिया में आज भी कोयला ही उर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। कम से कम आने वाले दो-तीन दशकों में हम कोयला का विकल्प तैयार नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि वह चाहे पैरिस का समझौता हो या फिर क्योटो में लिए गए निर्णय, हम उन पर आज तक अमल नहीं कर पाए हैं।

वैसे दुनिया में कोयले की खपत में कुछ हद तक कमी आई है। आज पूरी उर्जा का 42 प्रतिशत कोयले से आता है। अगर दुनिया के आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2010 में कोयले पर आया खर्च 134 अरब डॉलर था, जबकि वर्ष 2018 में इस पर 80 अरब डॉलर का खर्च हुआ। पर भारत में तत्परी नहीं बदली। यहां वर्ष 2010 में कुल खर्च करीब 6 अरब डॉलर था, जो 2018 में 8 अरब डॉलर हो गया। चीन ने जरूर इस मामले में तत्परता दिखाई। वह कोयले की खपत के मामले में काफी आगे था, लेकिन अब उसने इसे नियंत्रित किया है। वहां वर्ष 2010 में कोयले पर 50 अरब डॉलर खर्च हुए लेकिन 2018 तक



उसने यह खर्च 30 अरब डॉलर पर ला दिया। जाहिर है चीन ने वैश्विक समझौतों का थोड़ा-बहुत सम्मान किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। वहां 2019 में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की जो भी तैयारी हुई वह संतोषजनक नहीं है। भारत में गत वर्ष 1.8 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है, जो वर्ष 2018 की तुलना में कम है। दुनिया के बड़े देशों की ऊर्जा आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन उन्हें इसकी भरपाई के रूप में कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए ताकि इससे एकत्रित फंड से संयुक्त राष्ट्र विकासशील देशों को राहत दे सके।

दुर्भाग्य यह है कि बड़े देश इस तरह के योगदान से सीधे कतरा जाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे मुल्क किसी भी तरह की भागीदारी से अब पीछे हट रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील के राष्ट्रपतियों ने तो साफ कह दिया है कि जलवायु परिवर्तन जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उन राष्ट्रों का नेतृत्व वर्ग किसी न किसी उद्योग का हिस्सा होता है या उससे लाभान्वित होता है। इसलिए वह ऐसे निर्णय के साथ नहीं होता जिससे उसके व्यक्तिगत हित पर चोट पहुंचे। यही वजह है कि मांग और उत्पादन में इतने कम फर्क के बावजूद पर्याप्त बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती है। भारत विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं। भारत सरकार ने देश में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बढ़ते स्तर और पैरिस समझौता द्वारा तय किए गए मानकों को गंभीरता से लेते हुए वर्ष 2030 तक इसमें 33 से 35 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है। इसकी पूर्ति के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता को क्रमिक रूप से कम करने का फैसला किया है।

सूटोपु नवताल-5230	****
8 1	2 5
2	9
5	1 7 4
9 5	4 2
	3 9 6 7
7	8 1 5
	7 2 5 1
6	7
1 5	6 9

अपना ब्लॉग बंटा नजर आ रहा है वालीवुड!

लिमटी खरो। इस समय नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) पर माहौल गरमाया हुआ है। इन सभी मामलों में सियासी दलों के नुमाईदों के विचारों में भिन्नता तो दिख रही है साथ ही देश को परोक्ष रूप से दिशा देने वाले रूपहले पर्दे की दुनिया जिसे वालीवुड के नाम से जाना जाता है वह भी बटा हुआ ही दिख रहा है। इन मामलों में वालीवुड दो फाड़ ही नजर आ रहा है। इन मामलों में वालीवुड में भी गहमा गहमी महसूस की जा रही है। अभिनेता नसरुद्दीन शाह और अनुपम खेर के बीच जिस तरह की बयानबाजी चल रही है वह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानी जा सकती है। वालीवुड में फिल्मों के किरदार बनने वाले अभिनेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में उनके लाखों करोड़ों फेन हैं जो उनके द्वारा किए जाने वाले अभियान और कही जाने वाली बातों को अपने जीवन में अंगीकार भी करते हैं, वे लाखों करोड़ों लोगों के पायोनियर की भूमिका में भी नजर आते हैं।

